

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुग
सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2003—माघ 18, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर्ग समिति के प्रतिवेदन. (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम. (3) संसद के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक 146/2604/2002/एक/2.—श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री मिश्रा को

अपने कर्तव्यों के साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी, 2003

क्रमांक एफ ए 8-1/2001/एक (1).—इस विभाग के सम्-

संख्यक आदेश दिनांक 23-10-2002 को अधिक्रमित करते हुये जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने और जनसंपर्क तथा जन समस्याओं के निराकरण के लिये मंत्रि परिषद् के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों का प्रभार कालम 3 के अनुसार सौंपा जाता है :-

स.क्र.	मंत्री/राज्य मंत्री का नाम/विभाग	प्रभार के जिले का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नंद कुमार पटेल, मंत्री, गृह	रायपुर
2.	श्री भूपेश बघेल, मंत्री, राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को छोड़कर).	बिलासपुर
3.	श्री महेन्द्र कर्मा, मंत्री, उद्योग एवं खनिज (खनिज को छोड़कर).	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
4.	श्री माधव सिंह धुव, मंत्री, आदिम-जाति तथा अनुसूचित जाति विकास.	कांकेर (उत्तर बस्तर)
5.	श्री अमितेष्ट शुक्ल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.	महासमुंद
6.	श्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री, शिक्षा	दुर्ग
7.	श्री डी. पी. धृतलहरे, मंत्री, वन	कवर्धा
8.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	सरगुजा
9.	श्री चनेश राम राठिया, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	कोरिया
10.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री, निर्माण, पर्यावरण, एवं नगरीय विकास, विधि एवं विधायी तथा संसदीय कार्य.	रायगढ़
11.	श्री राम पुकार सिंह, मंत्री, उद्योग एवं खनिज, पर्यटन, संस्कृति, जनसंपर्क (उद्योग, पर्यटन एवं संस्कृति को छोड़कर).	जशपुर

(1)	(2)	(3)
12.	श्री गंगूराम बघेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व को छोड़कर).	जगदलपुर (यमनर)
13.	श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा शिक्षा (जल संसाधन को छोड़कर).	धमतनग
14.	श्री मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	गजनांदगांव
15.	डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा एवं जल संसाधन (ऊर्जा को छोड़कर).	जांजगांव चांपा
16.	श्री तुलेश्वर सिंह, राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.	कोरवा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 175/63/साप्रवि/2003/1/2. — श्री पी. गववन, प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज विभाग को दिनांक 13-1-2003 से 25-1-2003 (13 दिन) तक का अर्जित अवकाश व्याकृत किया जाता है. दिनांक 11, 12 जनवरी 03 एवं दिनांक 26 जनवरी सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राघवन को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव के पद पर वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री राघवन को अवकाश वेतन व अन्य भत्ता उसी प्रकार दिया जायेगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघवन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री पी. राघवन के अवकाश काल में, श्री के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, वन संस्कृति विभाग अपने कार्य के साथ-साथ वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्रमांक 181/2564/साप्रवि/2002/1/2.—डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद, तत्कालीन सचिव, छ. ग. शासन; कृषि विभाग को दिनांक 22-2-2002 से 1-3-2002 (8) दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे।

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रसाद यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते।

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक 204/2723/साप्रवि/2003/1/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 3001/2371/2002/1/2/साप्रवि, दिनांक 11-12-2002 द्वारा दिनांक 12-12-2002 से 20-12-2002 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी तारतम्य में श्रीमती ऋचा शर्मा को दिनांक 21-12-2002 से 24-12-2002 तक (13 दिन) तक का अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-12-2002 के शेष कालम (2) से (4) यथावत् रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-1-1/2003/(6)/11.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3101/सा. प्र. वि./2002/स्था./2/1 दिनांक 27

दिसम्बर, 2002 द्वारा श्री बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का स्थानान्तरण कलेक्टर, जशपुर के पद पर होने के कारण श्री एम. एस. धुर्वे विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज विभाग अपने कार्यों के साथ साथ आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छत्तीसगढ़ के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे। श्री एम. एस. धुर्वे को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा (4) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-58 (1) के तहत रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रदत्त होंगी।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पांडे, संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-5-28/दो/आट-परिवहन/2002.—चूंकि राज्य सरकार का मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,

अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा विकलांगों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वाहन जो निम्नानुसार निर्दिष्ट है को दिनांक 1-11-2000 से मोटरयान कर से छूट देती है।

वाहन का प्रकार - बस LGV (टाटा 709 मिनी बस स्कूल)।

वाहन क्रमांक- एम. पी. 23 जोए 3044.

इंजिन क्रमांक - 497D22 CTQ 727707

चेंसिस क्रमांक - 379035 CTQ 809592

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव।

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-5-29/दो/आठ-परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 21-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 21st January 2003

No. F-5-28/2/8-Transport/2002.—Whereas the State Govt. is of the opinion that is necessary to do so in the public interest:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the State Government hereby exempt the vehicles used for disabled as specified below from payment motor vehicle tax leviable under section 3 of the said Act with effect from 1-11-2000.

Vehicle Type-	Bus LGV (Tata 709 Mini Bus School).
Vehicle No. -	MP 23 GA 3044
Engine No. -	497D22 CTQ 727707
Chasis No. -	379035 CTQ 809592

By order and in the name of the Governor of
Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

फा. क्रमांक डी/538/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़

उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री डी. आर. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है।

Raipur, the 16th January 2003

F. No. D/538/21-B/Chh./2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure Code, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri D.R. Agrawal, Deputy Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Additional Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 543/डी-119/21-ब/छ. ग./2003.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1/1 8 6/2001/गोप./2002, दिनांक 3-1-2003 के परिप्रेक्ष्य में श्री दीग सिंह मरकाम, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण आयोग, दुर्ग की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापिस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आंगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2003

फा. क्रमांक 668/डी-2783/21-ब/छ. ग./2003.—राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिए जो कि नांचे दो गड सारणी के कॉलम (2) में वर्णित हैं, उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में दर्शाई गई वर्तमान रिटर्न फीस को पुनर्निश्चित कर कॉलम (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटर्न फीस) के रूप में दिनांक दिसम्बर, 2002 से नियत करता है :-

सारणी

कृषि विभाग

क्र.	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	महाधिवक्ता	रु. 21,000.00 (रु. इक्कीस हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 26,000.00 (रु. छब्बीस हजार केवल प्रतिमाह).
2.	अति. महा- धिवक्ता.	रु. 16,000.00 (रु. सोलह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 21,000.00 (रु. इक्कीस हजार केवल प्रतिमाह).
3.	उप-महा- धिवक्ता.	रु. 14,000.00 (रु. चौदह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 19,000.00 (रु. उन्नीस हजार केवल प्रतिमाह).
4.	शास. अधिवक्ता	रु. 12,000.00 (रु. बारह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 17,000.00 (रु. सत्रह हजार केवल प्रतिमाह).
5.	उप-शास. अधिवक्ता	रु. 10,000.00 (रु. दस हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 15,000.00 (रु. पन्द्रह हजार केवल प्रतिमाह).

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 40/S. R-31/B-3/IV/03 दिनांक 23-1-2003 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2003

क्रमांक 2503/डी-15/120/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की भाग 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ग्राम सिंघनपुर, तहसील बसना, जिला महाममूंद में स्थित खसरा नंबर 1536 को उपमण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करती है जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में की गई कोर्ड संरचना, आहता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है. उक्त अधिनियम की धारा-3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उपमण्डी प्रांगण की सीमा

- | | | |
|----------------|---|---------------------------|
| (1) उत्तर में | - | पशु. औषधालय |
| (2) दक्षिण में | - | श्रीमती मूला का कृषि भूमि |
| (3) पूर्व में | - | तालाब एवं घास भूमि |
| (4) पश्चिम में | - | एन. एच. 6 पहुंच मार्ग |

Raipur, the 10th January 2003

No. 2503/D-15/120/2002/14-3.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government hereby declare the two hectare land Khasra No. 1536 in Village Singhanpur, Tahsil Basna, District-Mahasamund including any structure enclosure open place or locality in market area, as a sub-market yard. The Notification under section 3 and 4 of the said Act has been previously published.

Boundary of Sub-Market Yard

- | | | |
|----|----------------|---------------------------------|
| 1. | On the North - | Veterinary Hospital |
| 2. | On the South - | Agriculture land of Smt. Mulla. |
| 3. | On the East - | Tank and gross land |
| 4. | On the West - | Approach Road to NH-6. |

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक 2559/बी-14/12/2002/14-2.—बीज अधिनियम 1966 (1966 का संख्या 54) भारत सरकार की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत कार्यरत बीज परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है, जहां उक्त अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का बीज नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विश्लेषण किया जाएगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

Raipur, the 15th January 2003

No. 2559/B-14/12/2002/14-2.—In the exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 4 of the Seed Act 1966 (No. 54 of 1966), the State Govt. hereby declares the Seed Testing Laboratory, Raipur working under C.G. Seed Certification Agency as a "State Seed Laboratory" where analysis of seeds of any notified kind or variety, as per seed rules and instruction issued from time to time by the State Govt. shall be carried out by seed analysis under the seed Act.

2. This notification will come into force with effect from its publication in the State Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 1-28/2002/(6)52.—राज्य शासन द्वारा संचालनालय ग्रामोद्योग की पद संरचना (सेट-अप) निम्नानुसार

क्र. (1)	पदनाम (2)	मान्य पद (3)	चतनमान (4)
1.	संचालक ग्रामोद्योग	1	14300-18300
2.	अपर संचालक	1	14300-18300
3.	संयुक्त संचालक, रेशम	1	12000-16500
4.	उप-संचालक, रेशम	2	10000-15200
5.	सहायक संचालक, रेशम.	2	8000-13500
6.	तकनीकी पर्यवेक्षक (फील्ड आफिसर)	2	5000-8000 पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
7.	संयुक्त संचालक, हाथ-करघा.	1	12000-16500
8.	उप-संचालक, हाथ-करघा.	2	10000-15200
9.	सहायक संचालक, हाथकरघा.	3	8000-13500
10.	सहा. हाथकरघा अधिकारी.	3	5000-8000
11.	हस्तशिल्प विकास अधिकारी.	1	8000-13500
12.	सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी.	1	5000-8000
13.	फील्ड इन्वेंस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	1	4500-7000
14.	मुख्य लेखा अधिकारी	1	10000-15200 प्रतिनियुक्ति में
15.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	2	5500-9000 प्रतिनियुक्ति/ग्यथा भग्नी.

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	3	4500-7000
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	2	5500-9000
18.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	4	4500-7000
19.	स्टेनो टायपिस्ट	2	3050-4590
20.	अधीक्षक	1	5000-8000
21.	सहायक अधीक्षक	2	4500-7000
22.	सहायक ग्रेड-1	3	4500-7000
23.	सहायक ग्रेड-2	5	4000-6000
24.	सहायक ग्रेड-3	17	3050-4590
25.	सहायक लेखाधिकारी	2	5000-8000 प्रतिनियुक्ति.
26.	लेखापाल	2	4000-6000
27.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3	3050-4590
28.	वाहन चालक	2	3050-4590
29.	दफ्तरी	1	2610-3510
30.	भृत्य	9	2550-3200
31.	चौकीदार	1	कलेक्टर दर
32.	फर्राश	1	— " —
33.	स्वीपर	1	— " —

2. उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जावेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग के पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.

(3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जावेंगे.

(4) दर्शाये गये सभी वेतनमान सही हैं. इस बात की पुष्टि कर ली गई है.

(5) ये सभी पद स्थाई पद होंगे.

3. रेशम संचालनालय की मांग संख्या-56 मुख्य शीर्ष 2851 ग्रामोद्योग एवं लघुशीर्ष-107 रेशम कोट पालन उद्योग योजना-(3778) रेशम उद्योग की योजना का क्रियान्वयन तथा हाथकरघा संचालनालय की मांग संख्या-56 ग्रामोद्योग एक राजस्व अनुभाग-2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-103-हाथ करघा उद्योग-0101-राज्य आयोजना 931-केन्द्रीय कार्यालय आयोजनेतर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 317/SR-20/9/ वित्त/चार/B-5/02 दिनांक 5-12-2002 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्रमांक 1942/मबावि/सावि/इमको/2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन/पंजीयन फर्म एंड सोसायटीज अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2-2-2002 को किया गया है. छत्तीसगढ़ महिला कोष का नाम दिनांक 13-12-2002 को परिवर्तित कर "इंदिरा महिला कोष" कर दिया गया है. अतः समस्त पत्र व्यवहार "इंदिरा महिला कोष" के नाम से किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्तम्भ 3 एवं स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट उद्योग एवं स्थानीय क्षेत्रों के लिए संग्रहक नियुक्त करता है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	उद्योग (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रम पदाधिकारी.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आने वाले समस्त उद्योग.	समस्त स्थानीय क्षेत्र

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the C.G. Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby appoints persons mentioned in column (2) of the schedule below to be the conciliators for the Industries and the local areas specified in the corresponding entries of column (3) and (4) thereof :—

SCHEDULE

No. (1)	Person (2)	Industries (3)	Local Areas (4)
1.	All Labour Officer appointed as such under sub-section (1) of section 6 of the C.G. Industrial Relation Act, 1960.	All Industries covered by the C. G. Industrial Relation Act, 1960.	All Local Areas

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	प्रथम अनुसूची (2)	अनुक्रमांक (3)	द्वितीय अनुसूची (4)
1.	श्री एच. आर. द्विवेदी	1.	श्री यू. के. कच्छप
2.	श्री एस. आर. दुग्गा	2.	श्री ताराचंद पटेल
3.	श्री एस. पी. वर्मा	3.	श्री अजय हेमंत देशमुख
4.	श्री एस. के. फुलेसर	4.	श्री रणवीर कपूर
5.	श्रीमती सविता मिश्रा	5.	श्री व्ही. आर. पटेल
6.	श्री एस. एल. जांगड़े		
7.	श्री देव प्रकाश तिवारी		
8.	श्री महेश राम		
9.	श्री यू. के. मेश्राम		
10.	श्रीमती अनिता गुप्ता		
11.	श्री भंवरसिंह बरिहा		
12.	श्री सूर्यभान सिंह पैकरा		
13.	श्री विकास सरोदे		

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Industries Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) in its application to the State of Chhattisgarh and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby appoints persons mentioned in the first schedule and the persons mentioned in second schedule to be respectively Labour Officers and Dy. Labour Officers :—

Sr. No. (1)	First Schedule (2)	Sr. No. (3)	Second Schedule (4)
1.	Shri H. R. Dwivedi	1.	Shri U. K. Kachhap
2.	Shri S. R. Dugga	2.	Shri Tara Chand Patel

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Shri S. P. Verma	3.	Shri A. H. Deshmukh
4.	Shri S. K. Phulesar	4.	Shri Ranveer Kapoor
5.	Smt. Savita Mishra	5.	Shri V. R. Patel
6.	Shri S. L. Jangde		
7.	Shri Deo Prakash Tiwari		
8.	Shri Mahesh Ram		
9.	Shri U. K. Meshram		
10.	Smt. Anita Gupta		
11.	Shri Bhanwar Singh Bariha		
12.	Shri Suryabhan Singh Paikra		
13.	Shri Vikas Sarode.		

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 25-ए की उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, उप श्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 या धारा 12 का उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय को प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Dispute Rules 1957 and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby authorizes the Deputy Labour Commissioner (In charge Officer of I. R. Section, H. Q.) Chhattisgarh, Raipur to acknowledge the receipt of every arbitration award of a Labour Court or Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it by him under Section 10 or Sub-section (5) of Section 12 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्र. 14 सन् 1947) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में दर्शित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के समस्त उद्योगों के लिए, जिनके राज्य शासन समर्पित शासन है, संसाधन अधिकारी नियुक्त करता है :-

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्रमायुक्त	प्रत्येक अधिकारी उसके समस्त स्थानीय अधिकारिता की सीमा में.
2.	सभी उप श्रमायुक्त	
3.	सभी सहायक श्रमायुक्त	
4.	सभी श्रम पदाधिकारी	
5.	सभी सहायक श्रम पदाधिकारी	

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Schedule below as Conciliation Officers for the areas specified against them in column (3) of the said schedule for all industries for which the State Government is the appropriate Government. :—

SCHEDULE

No. (1)	Person (2)	Industries (3)
1.	Labour Commissioner	Each officer within the limit of his local jurisdiction.
2.	All Dy. Labour Commissioners	
3.	All Asstt. Labour Commissioners	
4.	All Labour Officers	
5.	All Asstt. Labour Officers.	

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी आ. म. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 34 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-सी (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 33-C (1) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (5) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section, H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (3) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 10 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-13/2002/16.—राज्य शासन एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में नियम बनाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करती है.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. श्रमायुक्त | : | अध्यक्ष |
| 2. उपश्रमायुक्त "प्रशासन" | : | पदेन सचिव |
| 3. कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें,
रायपुर संभाग, रायपुर. | : | सदस्य |
| 4. कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर. | : | सदस्य |
| 5. प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर का प्रतिनिधि. | : | सदस्य |

Raipur, the 24th January 2003

No. F-11-13/2002/16.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby constitute following Expert Committee for making rules under this Act and its implementation in the State.

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Labour Commissioner | : | Chairperson |
| 2. Dy. Labour Commissioner
"Administration". | : | Officiating Secretary |
| 3. Executive Engineer
Rural Engineering Services
Raipur Division. | : | Member |
| 4. Executive Engineer
Public Works Deptt. Raipur. | : | Member |
| 5. Representative of Engineer
in Chief Water Resources Deptt. | : | Member |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. मूर्ति, सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 21 जनवरी 2003

प्र. क्र. 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, उक्त आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं. 7	0.50	प्रबंध संचालक, भो. सह. राकर उत्पा. कार. मर्या., कवर्धा.	राकर कारखाना हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्र. 518/भू-अर्जन/2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना प. ह. नं. 69/8	89.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के बांधपाए एवं डुबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्र. 915/भू-अर्जन/2002. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	अछोली प. ह. नं. 25	9.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	आमनेर मोती नाला डायवर्सन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुमति के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बरगढ़ प. ह. नं. 8	4.127	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुमति के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी प. ह. नं. 8	4.428	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/33. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	लोधिया प. ह. नं. 8.	5.781	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/34. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	दिमानी	5.262	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/सन् 02-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे डुमरपाली प. ह. नं. 13	0.507	महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. रायगढ़ क्षेत्र.	राबर्टसन रेल्वे स्टेशन के निकट साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/सन् 02-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प. ह. नं. 13	0.440	महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. रायगढ़ क्षेत्र.	रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/सन् 02-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रायगढ़	सारंगढ़	सालहेओना	14.217	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स हनुमान एग्रो इंडस्ट्रिज लिमिटेड, रायपुर (छ. ग.) के कागज कारखाना स्थापना हेतु भू-अर्जन.
		बिलाईगढ़	86.393		
		प. ह. नं. 29, 30	100.610		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1/अ-82/02-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
बिलासपुर	पेण्डारोड	आमाडांड	3.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	घाघरा जलाशय के डाउन स्ट्रीम में वृक्षारोपण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2/अ-82/02-03.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सिलपहरी	4.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	सिलपहरी जलाशय के बांध एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3/अ-82/02-03.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सकोला	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	पिपलामार	2.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के गाछा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 5/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	गिरारी	6.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के ड्रवान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	झावर	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्डारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के बांध पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 7/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सकोला	2.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्डारोड.	लोवर सोन व्यपवनन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

(1)

(2)

बिलासपुर, दिनांक 3 फरवरी 2003

क्रमांक 5 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्डुरोड

(ग) नगर/ग्राम-आमाडांड

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 97.48 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा

(एकड़ में)

(1)

(2)

377

0.92

381

0.76

512/2

1.52

513/2

0.20

519

1.75

523/1 ग

4.13

523/1 ड

3.21

523/1 ज

5.00

393/2

0.92

506/1

4.14

510/2

0.21

510/3

0.65

527/2

0.26

527/3

0.35

509

0.34

523/1 च

3.62

525/6

0.42

490/3

1.21

393/1

0.70

531/4

3.96

508/1

0.28

373/1

0.10

373/4

0.50

386/3

0.64

389

0.31

378

0.27

373/2

0.15

373/5

0.70

386/4

0.63

388/1

0.10

523/1 ख

4.00

369

0.60

510/5

0.20

393/3

0.97

521/2

0.60

518/2

0.14

521/3

0.88

534/1

1.34

399/2

0.06

384/3

0.38

397/2

0.56

398

0.14

400/2

0.05

402/7

0.54

522

1.06

529/1

1.46

525/4

0.42

388/3

0.24

538

0.25

533

0.73

511

0.74

525/5

0.42

372/2

0.58

510/4

0.65

527/4

0.52

528

0.08

523/1 क

1.06

394

0.68

526

1.30

393/4

0.65

(1)	(2)	(1)	(2)
388/2	0.35	508/2	0.37
390/1	0.26	525/7	0.42
392	0.90	539	0.10
391/1	0.54	399/1	0.02
534/2	0.60	379	0.90
536	0.08	382/2	2.06
537/2	0.30	384/2	1.98
373/3	0.15	397/1	0.56
373/6	0.30	529/2	0.24
374/2	0.55	400/1	0.05
376	0.03	372/3	0.55
375	0.40	530	0.58
391/3	0.90	521/1	0.40
387/2	0.68		
385	0.27	योग	112 97.48
382/1	1.45		
382/3	1.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय	
384/1	0.98	डूब क्षेत्र हेतु.	
380	0.44		
387/1	0.22	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,	
537/1	2.21	(राजस्व) पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
531/2	0.60		
513/4	0.95	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.	
503/5	1.02	आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
521/4	0.12		
523/1 घ	5.00		
535/2	1.57		
564/2	0.03		
525/3	0.14	कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं	
525/1	0.14	पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	
525/2	0.14	राजस्व विभाग	
565	0.25		
372/1	1.11		
510/1	0.20	रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2003	
527/1	0.30		
512/4	1.32	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य	
387/3	0.10	शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
390/2	0.30	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	
391/2	0.96	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984,	
537/3	0.19	क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया	
535/1	1.58	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
564/1	0.03	है :-	
395	1.25		

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		275/4	0.117
(क) जिला-रायगढ़		299/2	0.089
(ख) तहसील-रायगढ़		299/6	0.275
(ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली, कोकड़ीतराई, गेजामुड़ा		300/12 ख	0.109
(घ) लगभग क्षेत्रफल- कोसमपाली- 30.744		301/3	0.105
कोकड़ीतराई-15.328		301/8	0.142
गेजामुड़ा 2.469		301/13	0.057
		94/3	0.121
योग	48.541 हे.	111/2	0.182
		274/2	0.182
खसरा नम्बर	रकबा	275/5	0.267
	(हेक्टेयर में)	299/3	0.049
(1)	(2)	301/4	0.105
		301/9	0.105
		301/14	0.057
ग्राम कोसमपाली		301/18	0.085
		94/4	0.049
279/1	0.599	94/7	0.053
38/1	0.255	263/4	0.089
38/3	0.324	275/6	0.251
38/5	0.194	275/9	0.113
41	0.454	277/3	0.106
43/2	0.085	299/4	0.114
115/3	0.040	299/7	0.024
280/5	0.382	301/5	0.142
115/4	0.045	301/10	0.113
46	0.571	301/15	0.045
49/1	0.789	95/2	0.445
47	0.210	220	0.198
50/1	0.477	223	0.227
94/1	0.117	225	0.405
94/6	0.263	137	0.170
106/1	0.032	177/3	0.073
114/1	0.068	98	0.421
275/3	0.210	102	0.587
275/8	0.129	103	0.113
299/1	0.036	125/5	0.182
301/2	0.105	151/8	0.158
301/7	0.097	176/3	0.069
301/12	0.093	198/3	0.069
301/17	0.049	210/2	0.040
94/2	0.522	211/1 च	0.097
274/1	0.263	211/1 छ	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
211/1 ज	0.073	375/10	0.254
236/2	0.324	299/5	0.028
237/3	0.146	300/4	0.057
241/2	0.417	300/7	0.490
241/3		300/10 घ	0.393
241/4	0.036	300/14	0.170
105/1 क	0.162	300/16	0.174
125/3	0.445	300/17	0.291
125/4	0.028	301/19	0.041
130	0.425	301/20	0.113
254	0.239	279/3	0.394
156/3	0.061	284/1	0.160
165/1	0.032	283	0.178
250	0.109	285	0.101
249/1	0.004	300/3 ख	0.182
249/6	0.134	300/10 ख	0.198
249/8	0.040	300/5 क	0.089
249/10	0.040	300/8 क/1	0.793
249/12	0.040	300/10 क/1	0.301
249/14	0.008	300/10 ग	0.202
249/16	0.203	300/11 ख/2	0.486
249/5	0.081	300/15 क	0.404
249/7	0.182	300/18	0.627
249/9	0.190	280	0.405
249/11	0.061	280	0.202
249/13	0.061	300/11	0.340
249/15	0.008	300/11 ख/3	0.305
249/2	0.097	300/11 ग/2	0.064
249/3	0.065	280/2	0.202
249/4	0.178	300/11 क/2	0.303
265	0.057	284/2	0.202
253	0.243	300/3 क	0.064
255	0.178	300/3	0.162
300/10 क/2	0.364	300/13	0.405
258	0.178	300/15/ख	0.405
259/2	0.166	300/11 ग/3	0.405
300/3/2/क	0.405	200/2	0.081
300/3 क/4	0.057	200/3	0.081
262	0.466	202/2	0.348
275/1	0.061	238	0.413
301/1	0.057	293/3	0.441
275/2	0.676		
275/7	0.124		
		योग	30.744

(1)	(2)	(1)	(2)
ग्राम कोकड़ीतराई		274/2	0.008
		422	0.170
104/1 ख	0.202	423	0.607
109	0.522	424	0.291
112/1 क	0.324	425	0.421
178/2	0.081	426	
104/1 ज	0.202	278	0.567
104/1 झ	0.202	294	0.364
104/1 च	0.202	410/1	0.121
104/1 ङ	0.202	257	0.125
104/1 ट	0.202	410/2	0.425
106/1	0.097	273/2	0.053
106/2	0.089	277	0.170
112/1 क/1	0.328	412/2	0.300
124/3	0.101	416/2	
140/6	0.032	412/4	0.121
246/1	0.437	416/4	
394	0.182	417/2	0.073
427	0.417	414/2	0.445
428	0.821	273/1	0.458
114/5	0.081	276/1	0.142
124/2	0.299	261/1	0.073
233/1	0.057	261/2	0.077
133/2	0.134		
148/1	0.206		
209	0.069	योग	66 15.328
210	0.036		
412/3	0.040		
416/3	0.040		
274/1	0.146		
295/2	0.202	886/4	0.129
409	0.267	895/1	0.121
272/3	0.081	895/2	0.437
413	0.101	901	0.717
415	0.125	903/1	0.470
420	0.125	903/2	0.202
418	0.125	910/1	0.393
419	0.101		
421	0.817	योग	7 2.469
411	0.097		
259	0.372		
275/2	0.057		
248/2	0.235		
260/1	0.255		
276/2	0.142		
292	0.113		
260/2	0.243		

ग्राम गेजामुड़ा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आँद्यांगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

